रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2000/श्रावण 3, 1922
No. 488] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2000/SRAVANA 3, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2000

का.आ. 693(अ).—निम्नलिखित अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसके इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करने या सुझाव देने का इच्छुक व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए लिखित रूप में उसे सचिव, भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज सकेगा।

प्रारूप प्रस्थापनाएं

1. (क) महाबलेश्वर पंचगणी प्रदेश को अधिसूचित करने की यह प्रस्थापना की जाती है (पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के रूप में महाराष्ट्र सरकार की 19 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना में यथापरिभाषित) (उपाबंध के रूप में प्रतिलिपि संलग्न)। इस प्रदेश में महाबलेश्वर तहसील की सीमाओं और महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले की जावली तहसील के बोंडारबाडी भूतेगढ़ दानवाली, तलोसी और उबरी गांवों की सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित होगा।

(ख) वनों में सभी क्रियाकलाप (नगर पालिका क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(ग) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में विनियमित किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलापों की प्रतिस्थापना की जाती है।

2. (क) आंचलिक मास्टर प्लान :

(i) सम्पूर्ण अंचल के लिए एक मास्टर प्लान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी। मास्टर प्लान को प्रकाशित करने के लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जो महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम,

1966 के अधीन में विहित है। मास्टर प्लान उन परिसीमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से उपदर्शित कर सकेगी जहां उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।

(ii) उक्त मास्टर प्लान सभी विद्यमान वनों, हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, जैसे स्ट्राबेरी फार्मों, रसभरी फार्मों, फलोद्यानों, जनजातीय क्षेत्रों और अन्य पर्यावरणिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करेगी। हरित उपयोगों जैसे उद्यान, कृषि क्षेत्रों, कृषि, उद्यानों और अन्य ऐसे ही स्थानों से भूमि के उपयोग का कोई परिवर्तन मास्टर प्लान में गैर-हरित उपयोगों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(iii) महाबलेश्वर और पंचगणी नगर पालिका क्षेत्रों के भीतर और बाहर क्षेत्रों में उप आंचलिक मास्टर प्लान होंगे जो आंचलिक मास्टर प्लान के घटक के रूप में राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा सकेंगी और उस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाएगी।

इस उप आंचलिक मास्टर प्लान में गोथान क्षेत्रों के लिए भवन निर्माण विनियमों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(iv) ऊपर निर्दिष्ट आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन तक अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात, अनुज्ञेय ऊंचाई मंजिलों की अनुज्ञेय अधिकतम संख्या और अनुज्ञेय भू सीमा क्षेत्र के विद्यमान प्राचलों में कोई वृद्धि नहीं होगी और वन अंचल/हरित अंचल/कृषि अंचल में भी कोई कमी नहीं होगी। भवनों की आंत्यतिक ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होगी और मंजिलों की संख्या भूतल धन एक से अधिक नहीं होगी।

(ख) औद्योगिक ईकाईयां :

(i) उद्योगों की स्थिति केवल अभिहित औद्योगिक क्षेत्रों या संपदायों में होगी और वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा तय किए गए मार्गदर्शनों और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार होगी।

(ii) भविष्य में केवल अप्रदूषित, अपरिसंकटमय सेवा वाले ऐसे उद्योगों, एककों को, जो प्रसंस्कृत और तैयार चमड़े से जूते बनाते हों, तथा पुष्प कृषि उद्यान कृषि आधारित या कृषि आधारित ऐसे उद्योगों जो पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल से देशी माल से उत्पादों का उत्पादन करती हैं इस अंचल में अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु इनसे प्रदूषित बहिस्त्राव, उत्सर्जन या उनसे प्रभाव नहीं होता हो।

(iii) गैर नगर पालिका क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी अनुज्ञात किया जाएगा:

(क) लारजर डेरी, पाल्ट्री, मसरूम-रियरिंग और समवर्गी कृषि क्रियाकलापों की प्रकृति के अन्य यूनिटों और उससे संबद्ध सन्निर्माणों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जा सकेगा जो अधिकतम 1/8 निर्मित क्षेत्र के अधीन होगा जिसे आयुक्त, पुणे प्रभाग द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

(ख) लघु कृषि आधारित उद्योगों से सम्बद्ध संरचनाओं, स्थानीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और स्थानीय कृषि आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण या भंडारण की आवश्यकता से संबंधित क्रियाकलापों को भी अनुज्ञात किया जा सकेगा जो सामान्यतया "न लागू होने वाली" अनुज्ञा अपेक्षाओं और 1/8 में अधिकतम निर्मित क्षेत्र के अध्यधीन होगा।

(ग) खदान क्रिया और खनन : खदान क्रिया और खनन क्रियाकलाप इस क्षेत्र में प्रतिबंधित होंगे। पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में कोई नया खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा। तथापि मानिटरी समिति केवल स्थानीय निवासीय गृह निर्माण के संनिमार्ण और परम्परागत सड़क अनुरक्षण संकर्म के लिए अपेक्षित सामग्रियों की सीमित खदान क्रिया के लिए विशेष अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकारी होगी।

परन्तु यह कि ऐसी खदान क्रिया ऐसे पहाड़ी ढलानों पर जिसकी प्रवणता 15 डिग्री से अधिक हो या वन भूमि पर नहीं की जाती है।

(घ) वृक्ष : पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर की भूमि चाहे वन, सरकारी राजस्व या निजी भूमि हो वन भूमि की दशा में राज्य सरकार और सरकारी राजस्व और निजी भूमि की दशा में संबंधित जिला कलेक्टर की बिना पूर्व अनुज्ञा के जो उस प्रक्रिया के अनुसार होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी कोई वृक्ष नहीं गिराया जाएगा, परन्तु यह कि जिला कलेक्टर इस शक्ति को उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं करेगा।

(ङ) पर्यटन : पर्यटन क्रियाकलाप भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होंगे। पर्यटन मास्टर प्लान आंचलिक मास्टर प्लान का एक घटक रूप भी होगी।

पर्यटन मास्टर प्लान पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के चलाये जाने की क्षमता को विस्तृत अध्ययन पर आधारित होगी जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय

स्तरीय निगरानी समिति को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित कृत्य और उससे आनुषंगिक सभी बातें (समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाग निर्वारण अधिसूचना, तारीख 27 जनवरी, 1994 के उपबंधों के अधीन ऐसे कृत्यों को छोड़कर जिनका पालन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाना यथा अपेक्षित है) करने के लिए सशक्त करता है।

5. परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अधीन प्रत्यायोजित कृत्यों की बाबत किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील पर्यावरण और वन मंत्रालय को की जाएगी।

[फा.सं. जे.-20011/7/98-आई ए-III]

वी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव

उपाबंध

अधिसूचना

शहरी विकास विभाग

मंत्रालय, बंबई-400032

तारीख, 29 अप्रैल, 1983

महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, 1966

सं. टी पी एस 1982/4507(क)-यू डी 7 :—महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, 1966 (महाराष्ट्र का 1966 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "महाबलेश्वर पंचगनी प्रदेश" नामक एक प्रदेश का गठन करती है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की महाबलेश्वर तहसील की सीमाओं के भीतर का संपूर्ण क्षेत्र और सतारा जिले की जाओली तहसील के निम्नलिखित गांव होंगे :—

(1) बोंदारबाडी

(2) भूटेगढ़

(3) दानवाली

(4) तालोशी

(5) उम्बरी

2. उपर्युक्त अनुसार सम्मिलित क्षेत्र को दिखाने वाले महाबलेश्वर पंचगनी प्रदेश की सीमाओं को उपदर्शित करने वाले रेखांक की प्रति निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, अर्थात् :—

(1) नगर योजना निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूणे।

(2) सतारा का कलक्टर

(3) महाबलेश्वर और जाओली के तहसीलदार

(4) महाबलेश्वर म्युनिसिपल परिषद्

(5) पंचगनी म्युनिसिपल परिषद्

(6) नगर योजना सहायक निदेशक, सतारा

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेशानुसार और उनके नाम से ।

हस्ताक्षरित

(आर. बी. डोनाल्ड)

उप सचिव सरकार

महाबलेश्वर पंचगनी

पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंचल

महाबलेश्वर पंचगनी

क.	महाबलेश्वर पंचगनी प्रदेश का क्षेत्र	=	237.28 वर्ग कि.मी.
ख.	उपर्युक्त में		
	(1) महाबलेश्वर म्युनिसिपल क्षेत्र	=	19.55 वर्ग कि.मी.
	(2) पंचगनी म्युनिसिपल क्षेत्र	=	6.16 वर्ग कि.मी.
	(3) म्युनिसिपल सीमाओं से बाहर गाओथॉस	=	0.95 वर्ग कि.मी.
ग.	म्युनिसिपल सीमाओं से बाहर निवास जोन	=	1.66 वर्ग कि.मी.
घ.	वन अंचल	=	123.96 वर्ग कि.मी.
ङ.	हरित अंचल	=	83.72 वर्ग कि.मी.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2000

S.O. 693(E).— The following notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi 110 003.

DRAFT PROPOSALS

1 (a) It is proposed to notify the Mahableshwar Panchgani Region (as defined in the Government of Maharashtra notification of 29th April, 1983 as an Eco Sensitive Zone. (Copy attached as Annexure). The Region shall include the entire area within the boundaries of the Mahableshwar Tehsil and the villages of Bondarwadi,

Bhuteghar, Danwali, Taloshi and Umbri of Jaoli Tehsil of the Satara District in the Maharashtra state.

(b) All activities in the forests (both within and outside municipal areas) shall be governed by the provisions of the Indian Forests Act, 1927 (16 of 1927) and Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980). All activities in the sanctuaries and national parks shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

(c) The following activities are proposed to be regulated in the Eco-Sensitive Zone.

2. **(a) Zonal Master Plan :-**

(i) A Master plan for the entire Zone shall be prepared by the State Government and approved by the Ministry of Environment and Forests in the Government of India within a period of two years from the date of publication of this notification. The Master Plan shall be published by following a procedure similar to that prescribed under the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966. The Master Plan may clearly indicate those limited areas where industries shall be permitted.

(ii) The said Master Plan shall clearly demarcate all the existing forests, green areas, horticultural areas such as strawberry farms, raspberry farms, orchards, tribal areas, and other environmentally sensitive areas. No change of land use from green uses such as horticultural areas, agriculture, parks and other like places to non-green uses shall be permitted in the Master Plan.

(iii) The areas within and outside Mahableshwar and Panchgani municipal areas shall have Sub-Zonal Master Plans which may be prepared by the State Government as a component of the Zonal Master Plan and concurrence of the Ministry of Environment and Forests shall be obtained on this.

This Sub-Zonal Master Plan shall include building regulations for the gaothan areas.

(iv) Pending the preparation of and approval by the Ministry of Environment and Forests to the Zonal Master Plan and Sub-Zonal Master Plans referred to above, there shall be no increase in the existing parameters of permissible Floor Area

Ratio, permissible height, permissible maximum number of storeys and permissible ground coverage; and there shall also be no reduction in the Forest Zone/Green Zone/Agricultural Zone. Absolute height of buildings shall not exceed 9 metres and number of storeys shall not exceed ground plus one.

(b) Industrial Units :-

(i) Location of industries shall be only in the designated industrial areas or estates and has to be as per guidelines drawn up by the Government of Maharashtra as well as the guidelines issued from time to time by the Ministry of Environment and Forests.

(ii) In future only non polluting non hazardous service industries, units making footwear from processed and ready made leather, floriculture, horticulture based or agro based industries producing products from indigenous goods from the Eco Sensitive Zone shall be permitted in this zone:

Provided that these do not result in polluting effluent, emission or effect.

(iii) In the non municipal areas, the following shall also be permitted :

(a) Larger dairy, poultry, mush-room-rearing and other units in the nature of allied agricultural activities and structures connected therewith may be allowed with the prior permission of the competent authority subject to a maximum of $1/8^{th}$ built up area, relaxable by the Commissioner, Pune Division.

(b) Structures connected with small agro-based industries, activities related to the needs of the local village economy, and processing or storage of local agro-based products may be allowed subject to the usual "Not Applicable" permission requirements and a maximum built up area of $1/8^{th}$.

(c) Quarrying and Mining :- Quarrying and Mining activities shall be banned in this area. No fresh mining lease shall be granted in the Eco Sensitive Zone. However, the Monitoring Committee shall be the authority to give special permission for limited quarrying of materials required for the construction of local residential housing and traditional road maintenance work only;

Provided that such quarrying is not done on hill slopes having a gradient of more than 15 degrees or on forest lands.

(d) Trees :-There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or private lands within the Eco-Sensitive Zone, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land, as per procedure which shall be prescribed by the State Government, provided that the District Collector shall not delegate this power to any subordinate officer below the rank of Sub-Divisional Officer.

(e) Tourism :-Tourism activities shall be as per a Tourism Master Plan to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Ministry of Tourism of Government of India and approved by the Ministry of Environment and Forests. The Tourism Master Plan shall also form a component of the Zonal Master Plan.

The Tourism Master Plan shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Eco-Sensitive Zone which may be carried out by the State Government and submitted to the Ministry of Environment and Forests for approval within two years of the date of this notification. All new tourism activities, developments for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of this tourism plan or carrying capacity study. Till the Tourism Master Plan is submitted to Ministry of Environment and Forests for approval, new tourism activities and developments for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only after a detailed analysis is carried out and approved by the Monitoring Committee subject to guidelines laid down by Ministry of Environment and Forests.

(f) Natural Heritage :- The sites of valuable natural heritage in the zone shall be identified, particularly rock formations, waterfalls, pools, gorges, groves, caves, points, walks, rides etc. and plans for their conservation in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and Sub Zonal Master Plans. Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to discourage construction activities at or near these sites including under the garb of providing tourist facilities. All the gene pool reserve areas

in the zone shall be preserved. The State Government may draw up proper plans for their conservation or preservation within one year from the date of publication of this notification. These plans shall form a part of the Zonal Master Plan and Sub-Zonal Master Plans.

(g) Man-made heritage :- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetical, and cultural significance shall be identified and plans for their conservation, particularly their exteriors (and wherever deemed appropriate their interiors also) shall be prepared and incorporated in the Zonal Master Plan and Sub-Zonal Master Plans within one year from the date of publication of this notification. Guidelines may be drawn up by the State Government to regulate building and other activities in the Zone, particularly in Mahableshwar and Panchgani municipal limits and in Kshetre Mahableshwar, so that the special character and distinct ambience of the towns and the eco sensitive zone is maintained.

(h) Development or construction activity at or around heritage sites (both natural and man-made) shall be regulated in accordance with the Draft Model Regulations for Conservation of Natural and Man-made Heritage formulated by the Ministry of Environment and Forests in 1995 as amended from time to time and circulated to all State Governments and Union territory Administrations).

(i) Ground Water:- Extraction of ground water shall be permitted only for the bona fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot after obtaining permission from the State Ground Water Board. No sale of ground water shall be permitted.

(j) Use of plastics :- The use of plastics within the Eco Sensitive Zone shall be regulated by the Monitoring Committee.

(k) Protection of Hill Slopes :- There shall be no construction on hill slopes having a gradient of more than 15 degrees.

(l) Discharge of effluents :- The discharge of any untreated effluent is prohibited within the Eco Sensitive Zone. No effluent, either treated or untreated, shall be permitted to be discharged into the forests or any water source within the zone.

(m) Solid Wastes :- The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components. The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture; the inorganic material may be disposed of at environmentally acceptable locations. No burning or incineration of solid wastes can be undertaken without prior permission. It is clarified that the term solid wastes include domestic, industrial, commercial and garden wastes.

3 (a) The Government of India shall constitute a High Level Monitoring Committee to ensure compliance with the provisions of this notification.

(b) It shall be the duty of the Monitoring Committee to file complaints under section 19 of the said Act if offences under the said Act come to its notice.

(c) The Committee or any officer or member of the Monitoring Committee authorised by the Committee shall be authorised to file complaints under the said Act.

4. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with section 23 of the said Act, the Ministry of Environment and Forests, Government of India empowers the Urban Development Department, Government of Maharashtra and the High Level Monitoring Committee to discharge the functions specifically enumerated in this notification and to do all things incidental thereto, (except the functions as are required to be performed by the Central Government under the provisions of the Environment Impact Assessment notification of 27th January, 1994 as amended from time to time).

5. Provided that in respect of functions delegated under this notification, an appeal from any order shall lie to the Ministry of Environment and Forests.

[F. No. J-20011/7/98/IA-III]

V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

ANNEXURE

NOTIFICATION

Urban Development Department
Mantralaya, Bombay 400 032

Dated : 29th April 1983

Maharashtra Regional and Town Planning Act. 1966

No. TPS. 1982/4507 (a)-UD 7 : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"), to Government of Maharashtra, hereby establishes a Region for the purpose of the said Act to be named as the "Mahableshwar Panchgani Region" which shall include the entire area within the boundaries of the Mahableshwar Tehsil and the villages of -

(1) Bondarwadi
(2) Bhuteghar
(3) Danwali
(4) Taloshi
(5) Umbri

of Jaoli Tahsil of the Satara District in the Maharashtra State.

2 A copy of the plan showing boundaries of the Mahableshwar Panchgani Region showing the area included as aforesaid is available for inspection at offices of the following officers, namely :

(1) The Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune
(2) The Collector of Satara
(3) The Tahasildars of Mahableshwar and Jhaoli
(4) The Municipal Council, Mahableshwar
(5) The Municipal Council, Panchgani
(6) The Assistant Director of Town Planning, Satara

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

Sd/-
(R B. Donald)
Deputy Secretary to Government

MAHABLESHWAR PANCHGANI

ECO-SENSITIVE ZONE

MAHABLESHWAR PANCHGANI

A.	Area of Mahableshwar Panchgani Region	=	237.28 sq. kms
B.	Of the above		
	(1) Mahableshwar Municipal Area	=	19.55 sq. kms
	(2) Panchgani Municipal Area	=	6.16 sq. kms
	(3) Gaothans outside Municipal limits	=	0.95 sq. kms
C.	Residential Zone outside Municipal limits	=	1.66 sq. kms
D.	Forest Zone	=	123.96 sq. kms
E.	Green Zone	=	83.72 sq. kms

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.